जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका

डॉ. राकेश कुमार सामोता*

प्रस्तावना

किसी भी क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास उस क्षेत्र के मानव संसाधन पर निर्भर करता है। इसके उचित उपयोग के लिए अनेक योजनाएँ आईं जिसमें सबसे मुख्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 को अधिसूचित हुए 12 वर्ष हो गये जबसे यह अधिनियम लागू हुआ, देश के निर्धनतम जिलों में लाखों लोगों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाला कानून है जो गरीब ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को कानूनी तौर पर बाध्य करता है।

नरेगा 2 फरवरी, 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया। योजना का प्रारम्भ आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से हुआ। जिसे 2007–08 में 300 अतिरिक्त जिलों में लागू किया गया इसी द्वितीय चरण में जयपुर जिले को शामिल किया गया।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, जिससे ग्रामीण इलाकों में विभिन्न उत्पादों की खपत को बढ़ावा मिला है। मनरेगा के अन्तर्गत भूमि सुधार पर जोर दिया गया है जिसके अन्तर्गत् वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है जिससे पर्यावरण सन्तुलन में मदद मिलेगी ग्रामीण तबके के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में मदद मिल रही है और सतत् विकास की ओर बढ़ता प्रतीत हो रहा है।

भौगोलिक स्थिति–जयपुर राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक मैदानी जिला है। अक्षांश व देशान्तर स्थिति–अक्षांश 26ह्23ञ से 27ह्51ञ उत्तरी अक्षांश देशान्तर 74ह्55ञ से 76ह्50ञ पूर्वी देशान्तर है। क्षेत्रफल–11143 वर्ग किमी जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत भाग है।औसत तापमान 24.26ह्ब के बीच रहता है। औसत वर्षा 60–80 सेमी के मध्य रहती है। जलवायु आद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मिट्टी–भूरी कछारी है। जनसंख्या–जनगणना 2011 के अनुसार 66.63 लाख जो राजस्थान की कुल जनसंख्या 9.71 प्रतिशत भाग है। अपवाह तंत्र–बाण गंगा, बांडी, ढूंढ, मोरेल, साबी, डाई, सखा, माशी आदि नदियाँ बहती हैं।

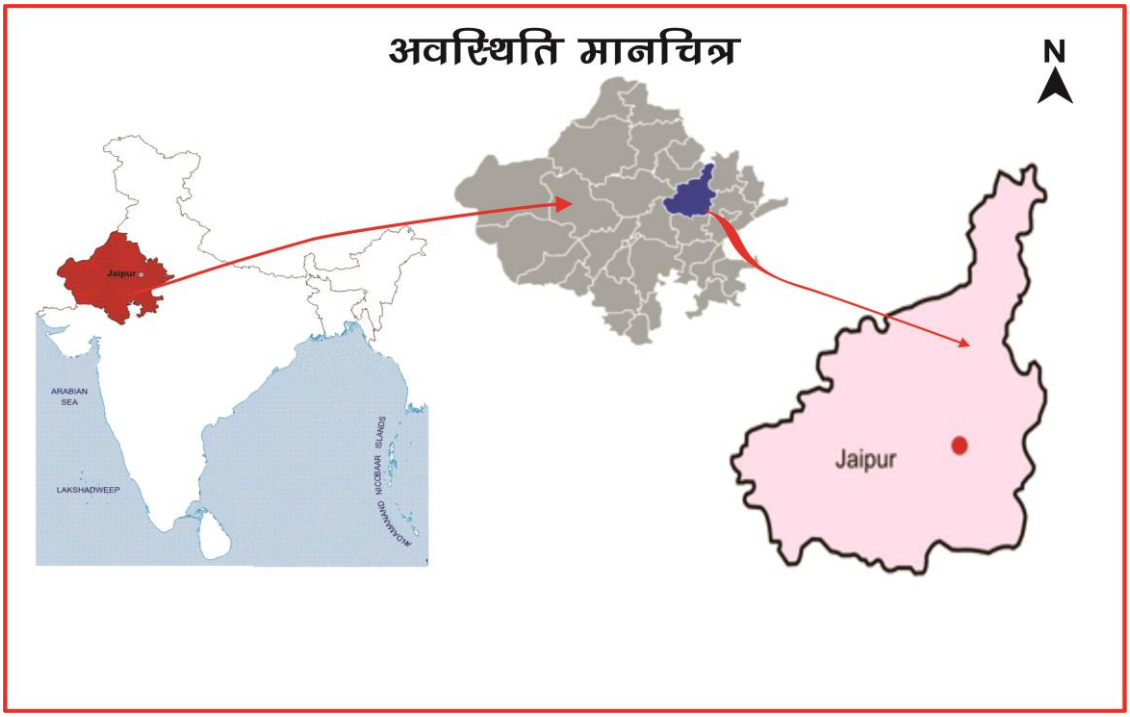

प्रशासकीय इकाईयाँ

1. उपखण्ड–13

* डॉ. राकेश कुमार सामोता:–डॉक्टरेट, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान

2. तहसील–16
3. विकास खण्ड–15
4. ग्राम (आबाद) 2348
5. ग्राम (गैर–आबाद) 54
6. कस्बे–11
7. नगरपालिका/नगरपरिषद्–10
8. नगर निगम–1

शोध की परिकल्पना

1. मनरेगा से आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।
2. मनरेगा से सामाजिक प्रवास रूका है।
3. मनरेगा से अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता में कमी हुई है।

शोध के उद्देश्य एवं उपयोगिता

1. मनरेगा के पूर्व एवं मनरेगा के पश्चात् ग्रामीण जीवन की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. मनरेगा के फलस्वरूप जयपुर जिले में भूमि उपयोग में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक प्रवास पर लगी रोक का अध्ययन।
4. पर्यावरण एवं जल प्रबन्धन में आये परिवर्तन का अध्ययन करना।

जयपुर जिले में आर्थिक विकास मनरेगा की भूमिका

आंकड़ों के अनुसार मनरेगा ने 32 प्रतिशत तक ग्रामीण गरीबी को कम किया है। जबकि 14 मिलियन को गरीबी रेखा के नीचे जाने से रोका है। मनरेगा के चलते जहाँ ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि हुई है। वही श्रमिकों द्वारा मोलभाव की क्षमता भी बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार 2004–05 से 2014–15 के दौरान ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि देखी गई इसका परिणाम यह हुआ कि एक बड़ी ग्रामीण आबादी की कुल आय में वृद्धि हुई फलस्वरूप उनकी क्रय शक्ति बढ़ी जिससे मांग में वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही घरेलू बचत में वृद्धि हुई। गौरतलब है कि मनरेगा ने ग्रामीण जनसंख्या के वित्तीय समावेशन में बड़ी भूमिका निभाई है। जयपुर जिले के ऐसे गांव एवं परिवार जिन्होंने मनरेगा में भाग लिया उनकी शाहूकारों पर निर्भरता काफी घटी है। आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में काम करने वाले प्रतिभागियों में से 48 प्रतिशत लोगों ने 2004–05 तक साहूकारों से कर्ज लिया था लेकिन वर्ष 2014–15 के आंकड़ा घटकर 19 प्रतिशत रह गया।

इसी दौरान मनरेगा से जुड़े लोगों द्वारा संगठित क्षेत्र में ऋण लेने में इजाफा हुआ और यह 24 प्रतिशत से 34 प्रतिशत हो गई। इसका एक मुख्य कारण मनरेगा द्वारा सीधे भुगतान हेतु बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस खातों का प्रयोग करना रहा होगा इतना ही नहीं जिन गांवों में मनरेगा के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ मनरेगा में कार्य कर रहे गरीब घरों के बच्चों के शिक्षा स्तर में बेहतर सुधार भी दर्ज किया गया। जिले में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हुई तथा अकुशल श्रमिकों की बेरोजगारी में कम आयी।

जयपुर जिले के सामाजिक विकास में मनरेगा की भूमिका

मनरेगा के लागू होने के बाद गांवों से शहरों की ओर हो रहे प्रवास में अब तक निरन्तर कमी आ रही है। गांवों के विकास के लिये इस कार्यक्रम में रोजगार के साथ–साथ सामाजिक एवं सृजनात्मक कार्य भी किये जाते हैं। सामाजिक विकास के लिये इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण में भी मनरेगा की महत्त्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। जैसा कि प्रावधान है कि मनरेगा लाभार्थियों में एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है। अतः इसका स्पष्ट लाभ महिलाओं को मिला है। अतः निश्चित ही मनरेगा ने महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारा है।

देखा जाए तो सामाजिक समता को स्थापित करने में भी नरेगा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जयपुर जिले स्तर पर इसके अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी काफी अधिक रही ध्यातव्य है कि वित्त वर्ष 2010–11 के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी क्रमशः 31 प्रतिशत व 21 प्रतिशत रही थी हालाकि इसके बाद इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई परन्तु इसके बावजूद अनुसूचित

जातियों की भागीदारी 20 प्रतिशत से अधिक रही है। वित्त वर्ष 2015–16 के लिये अनुसूचित जातियों की भागीदारी 23 प्रतिशत जबकि अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी 17 प्रतिशत है।

मनरेगा में कुछ खामियाँ

1. भुगतान में विलम्ब और फर्जी हाजिरी रजिस्टर बनाकर फंड की निकासी करना।
2. मनरेगा के अन्तर्गत ज्यादातर अनुत्पादक कार्य किये जाते हैं।
3. ग्रामीण मजदूरी में हुई वृद्धि का श्रेय मनरेगा को दिया जाता है जिससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
4. मनरेगा के खराब कार्यान्वयन का ही नतीजा है कि अब तक 70 प्रतिशत गरीब मनरेगा में सहभागिता से वंचित है।

मनरेगा में निष्कर्ष एवं सुझाव

1. प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के कार्यों की योजना बनाने का व्यावहारिक रूप से ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाकर ही सम्भव हो सकता है।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों के लिए तैयार किये जाने वाले 'सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट' में समाज में वैज्ञानिकों की राय सम्मिलित किया जाना चाहिए।
3. मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की योजना इस प्रकार बनायी जानी चाहिए उन ग्रामों में भविष्य में रोजगार के स्थायी साधनों का विकास हो सके।
4. इस कार्यक्रम में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार रोकने के लिये सामाजिक अंकेक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- इपस्टेन, टी.एस. 1964; इकोनोमिक डवलपमेन्ट एवं सोशल चैनज इन साउथ इण्डिया, मानचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, यू.एस.ए।
- किशोर, चन्द 1990; ग्रामीण राजस्थान में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भौगोलिक आधार, प्रकाशित पीएच.डी. थीसिस, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- जाट, बी.सी. 2003; भूगोल और आप (द्विमासिक पत्रिका, 2010), आइरिश पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- योजना (मासिक पत्रिका) अगस्त, 2008, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, दिल्ली।
- कुरूक्षेत्र (मासिक पत्रिका, दिसम्बर 2009) प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, दिल्ली।